

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 18 अगस्त 2026, समय 13:05 (5 मिनट))

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैनुफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दी है। इससे करीब 7 हजार 9 सौ करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान है।

इन मंजूरीयों से 82 हजार करोड़ रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन और 9 हजार पांच सौ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से आए हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7 तथा महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। इन परियोजनाओं में एसीटिलीन ब्लैक, स्पीकर-माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।

श्री वैष्णव ने बताया कि इन 31 मंजूरीयों के साथ ईसीएमएस के तहत अब तक 106 कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने 59 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था, जबकि अब यह 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

उन्होंने कहा कि नई मंजूरीयां घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और उन्नत विनिर्माण क्षमता विकसित करने में मदद करेंगी, जिससे भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने को और गति मिलेगी।

भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परम्परा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए।

हरियाणा सरकार ने एक विशेष वितीय प्रणाली तैयार की है। ताकि विजिलेंस ट्रैप के लिए रिश्वत की रकम देने वाले शिकायतकर्ताओं को भ्रष्टाचार की जांच के दौरान अपनी जेब से खर्चे पैसे जल्दी वापिस मिल सके।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी एक अधिसूचना के ज़रिए, सरकार ने 'हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो रिवॉल्विंग फंड' बनाया है। इसका मकसद खास तौर पर उन शिकायतकर्ताओं को रिश्वत की रकम वापस करना है जिन्होंने ट्रैप बिछाने के लिए पैसे दिए थे। इस फंड का प्रबंधन हरियाणा के राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के महानिदेशक करेंगे। इस कदम से उन नागरिकों के लिए पैसे की वापसी का एक औपचारिक तरीका बन गया है, जिनका पैसा रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है।

चंडीगढ़ में 'हर घर तिरंगा' अभियान कल सेक्टर 42 स्थित न्यू लेक में आयोजित भव्य एवं उत्साहपूर्ण समापन समारोह के साथ समापन हो गया। कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ प्रशासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित इस रैली में समारोह का एक प्रमुख आकर्षण बाइक एवं विंटेज कार रैली रही। इसके उपरांत प्रशासक ने आयोजन स्थल पर लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों और प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत हथियारों और ड्रोन की प्रदर्शनी के साथ-साथ आईटीबीपी द्वारा आयोजित हथियार प्रदर्शनी, कराटे प्रदर्शन और डॉग शो भी देखा।

